शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई–पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक–45 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 28–4 नवम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार की परफॉरमैन्स को फिर बनाया चुनावी मुद्दा

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल सरकार की परफॉरमैन्स को महाराष्ट्र और झारखण्ड विधानसभा चुनावों में फिर मुद्दा बनाकर उछाला है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने के लिये जो गारंटीयां प्रदेश की जनता को दी थी आज उन्हें पूरा करने के लिये सरकार का वितीय सन्तुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। आज हिमाचल के कर्मचारियों को अपने वेतन भत्तों और एरियर के लिये सड़कों पर आना पड़ रहा है। कांग्रेस सत्ता में आने के लिये झूठी गारंटीयां देती है अब यह तथ्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी स्वीकार कर लिया है। खड़गे ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि गारंटीयां बजट को देखकर दी जानी चाहिये। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री के आरोप के जवाब में कहा है कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव में दी दस में से पांच गारंटीयां पूरी कर दी हैं। इन पांच गारंटीयों में कर्मचारियों की ओल्ड पैन्शन योजना बहाल कर दी है। पात्र महिलाओं को 1500 रूपये मासिक भत्ता, कक्षा एक से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करना, 680 करोड़ का स्टार्टअप फण्ड स्थापित करना, दूध का न्यूनतम वेतन मूल्य लागू करना शामिल है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि की गयी है। अर्थव्यवस्था में 23 प्रतिशत की बढ़ौतरी करके 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। मुख्यमंत्री ने पांच गारंटीयां पूरी कर देने का दावा किया है। लेकिन इस दावे पर उस समय स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है जब यह सामने आता है कि गारंटीयां लागू होने के बाद भी कांग्रेस लोकसभा की चारों सीटें क्यों हार गयी। क्या गारंटीयां लागू होने का प्रदेश के कर्मचारियों और जनता पर कोई असर नहीं हुआ? सुक्खू सरकार ने मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में कर्मचारियों के लिये ओल्ड पैन्शन बहाल कर दी थी। सरकार ने सारे कर्मचारीयों के लिये ओल्ड पैन्शन लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन आज भी कुछ निगमों, बोर्डो और स्थानीय निकायों के कर्मचारी ओल्ड पैन्शन की मांग कर रहे हैं परन्तु सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रही है। स्मरणीय है की प्रदेश के कर्मचारियों के लिये न्यू पैन्शन योजना 15 मई 2003 से लागू की गयी थी। इसके मुताबिक जो कर्मचारी 2004 से सरकारी सेवा में आये उन पर न्यू पैन्शन स्कीम लागू हुई और अब उन्हीं को ओल्ड पैन्शन के दायरे में लाया गया। 2003 तक के कर्मचारी तो पहले ही ओल्ड पैन्शन के दायरे में थे। पैन्शन तो सेवानिवृत्ति पर ही मिलनी है। ऐसे में 2004 से सरकारी सेवा में आये कितने लोग रिटायर हो गये होंगे जिनको ओल्ड पैन्शन का व्यवहारिक लाभ सरकार को देना पड़ा होगा। क्योंकि 2004 में लगे कर्मचारियों के 20 वर्ष तो 2024 में पूरे होंगे इसलिए अभी तक ओल्ड पैन्शन की देनदारी तो बहुत कम आयी होगी। दावा करने के लिये तो ठीक है परन्तु व्यवहारिक तौर पर यह पूरा सच नहीं है। इसी तरह 18 वर्ष से 60 वर्ष की हर महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की बात की गयी थी और प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलना था। परन्तु अब जब इस योजना को लागू करने की बात उठी तो इसके लिये जो योजना अधिसूचित की गयी है उसमें पात्रता के लिये इतने राइडर लगा दिये गये हैं कि जिससे व्यवहारिक रूप से यह आंकड़ा 22 लाख से घटकर शायद दो तीन लाख तक भी नहीं रह जायेगा। फिर पूरे प्रदेश में इसे एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है। इसका असर सरकार के पक्ष में उतना नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति 680 करोड़ के स्टार्टअप फण्ड की है। सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना प्रदेश के युवाओं के लिये अधिसूचित की थी। शुरू में इस योजना का संचालन श्रम विभाग को दिया गया था। फिर हिम ऊर्जा को बीच में लाया गया। हिम ऊर्जा से यह योजना बिजली बोर्ड पहुंची परन्तु व्यवहार में शायद एक भी युवा इस योजना के तहत कोई सोलर प्लांट नहीं लगा पाया है। इसी तरह दूध का समर्थन मूल्य तो कागजों में तय हो गया परन्तु व्यवहारिक रूप से यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि गांव में लोगों के पास दुधारू पशु भी पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं। यह योजना शायद जायका के माध्यम से कांगड़ा में लगाये जा रहे मिल्क प्लांट को सपोर्ट देने के लिये लायी गयी थी। परंतु अभी कांगड़ा का यह प्रस्तावित प्लांट व्यवहारिक शक्ल लेने में वक्त लगा देगा। हालांकि पूर्व मुख्य सचिव रामसुभग सिंह इस पर काम कर रहे हैं।

सरकार ने पांच लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी थी। प्रदेश में सरकार ही रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। सरकार ने आते ही मंत्री स्तर की एक कमेटी बनाकर सरकार में खाली पदों की जानकारी दी थी। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में 70,000 पद खाली है। सरकार 20,000 से अधिक पद भरने का दावा कर रही है। लेकिन विधानसभा में इस आश्य के आये हर प्रश्न का जवाब सूचना एकत्रित की जा रही है देने से सरकार की कथनी और करनी का अन्तर सामने आ गया है। अब बिजली बोर्ड में आउटसोर्स पर रखे 81 ड्राइवरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाने से सरकार की नीयत पर शक होना स्वभाविक हो जाता है। क्योंकि एक ओर सरकार आउटसोर्स कर्मचारीयों को बाहर निकाल रही है और दूसरी ओर आउटसोर्स भर्ती के लिए कंपनियों से आवेदन मांग रही है। इस परिदृश्य में यदि प्रधानमंत्री सरकार की कार्यशाली को चुनावी मुद्दा बना कर उछाले तो उस पर सवाल उठाना कठिन होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं दावा किया है कि सरकार ने 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है। यह अतिरिक्त राजस्व लोगों पर परोक्ष/ अपरोक्ष में करों का बोझ बढ़ाकर ही अर्जित किया गया है। इसका लोगों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है जो आने वाले दिनों में सरकार और कार्यकर्ताओं की परेशानी बढ़ायेगा।

> ☞ मुख्यमंत्री के पांच गारंटीयां लागू करने के दावों पर उठे सवाल
>
> ☞ क्या 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व लोगों पर करों का बोझ बढ़ाकर अर्जित नहीं किया गया?

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकसित होंगे आदर्श स्वास्थ्य संस्थानः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आम जनमानस को घर-द्वार के निकट उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।

इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत कर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें मशीनरी एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए एक-एक करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के परिधि गृह में टोंगलेंग की मोबाइल क्लीनिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के उपरांत कहा कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना के अन्तर्गत कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों में केजुएलटी विभाग को स्तरोन्नत कर आपातकालीन मेडिसिन विभाग बनाए जा रहे हैं। कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं के साथ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां तथा उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए 42 दवाइयां निशुल्क प्रदान की जा रही हैं। इन दवाओं को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में भी शामिल किया गया है।

राज्यपाल ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में सरदार बल्लभाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार बल्लभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता की मिसाल थे। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए जीवनभर संघर्ष किया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन के कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।

शपथ समारोह के दौरान सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को बनाए रखने, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और देशभक्ति की भावना का जन-जन में प्रसार करने का प्रण लिया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी. पी. वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नाम दर्ज, दावे व आक्षेप करना सुनिश्चित करें

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश नन्दिता गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचक अधिकारियों के कार्यालयों में किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में जनसाधारण द्वारा दावे व आक्षेप तथा निःशुल्क निरीक्षण का कार्य 28 नवम्बर, 2024 तक किया जाएगा। निरीक्षण, दावे व आक्षेप फॉर्म 6, 7 व 8 पर दर्ज करने के लिए उल्लेखित स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी पात्र नागरिक 1 अक्तूबर, 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो भी मतदाता सूचि में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 9 व 10 नवम्बर, 2024 तथा 23 व 24 नवम्बर, 2024 शनिवार व रविवार के दिनों में विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं, ताकि सभी छूटे हुए पात्र नागरिक अपना तथा अपने परिवार के पात्र व्यक्ति का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचि में दर्ज करवाने, अशुद्ध प्रविष्टियों में शुद्धिकरण तथा परिवार के अपात्र नागरिक का नाम मतदाता सूचि से हटाए जाना सुनिश्चित कर सकें। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र जो अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, यानी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईटीआई, नर्सिंग संस्थानों, डाइट, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 13 और 26 नवंबर 2024 को बीएलओज हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।

वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in. में भी कर सकता है। वेब साईट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से online फार्म नाम दर्ज करने, अपमार्जन तथा संशोधन हेतु, भरे जा सकते है। दावे अथवा आक्षेपों का निपटारा 24 दिसम्बर, 2024 तक किया जाएगा, जबकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 तक किया जाएगा।

उन्होंने प्रदेश के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वंय सेवी संगठनों, महिला एवम् युवा मंडलों से यह आवाहन किया है कि वह प्रारूप प्रकाशन की अवधि दिनांक 29-10-2024 (मंगलवार) से 28-11-2024 (वीरवार) तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण अपने सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर जाकर कर लें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने, अशुद्ध प्रविष्टियों में शुद्धि करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके।

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के निःशुल्क टेलीफोन सेवा कॉल सेंटर फ्री नंबर 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का त्यौहार सभी के जीवन को प्रकाशमान करता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का संदेश देता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह त्यौहार प्रदेशवासियों के जीवन में अपार खुशियां लाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने शुभ कामना संदेश में कहा कि दीपावली का त्यौहार लोगों को सद्भावना, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समृद्धि और धन-धान्य का यह पर्व सभी के जीवन में उल्लास और प्रसन्नता लाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार एकता के बंधन को मज़बूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने लोगों से त्यौहार को पारंपरिक और पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ से मनाने का आहवान भी किया।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि प्रकाश का यह उत्सव प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा।

मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों ने भी दीपावली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं।

31 दिसम्बर तक आधार नम्बर को राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य

शिमला/शैल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशक राम कुमार गौतम ने बताया कि विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के माध्यम से राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुसार सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत दिनों में आधार से संबंधित तकनीकी एवं अन्य समस्याओं के दृष्टिगत विभाग द्वारा आधार संख्या पंजीकरण व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 30 सितम्बर, 2024 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अभी भी कुछ उपभोक्ताओं द्वारा किसी कारणवश उनके राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या को पंजीकृत नहीं किया जा सका है।

उन्होंने आग्रह किया कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वह अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान/लोक मित्र केंद्र पर जा कर या ई-केवाईसी पीडीएस एचपी एंडरॉयड मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया 31 दिसम्बर, 2024 से पहले करवाएं। यदि कोई अपना आधार नम्बर 31 दिसम्बर, 2024 तक राशन कार्ड से नहीं जोड़ता है तो उनके राशन कार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा और आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही राशन कार्ड को फिर से शुरू किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट/ पारदर्शिता पोर्टल https://epds.hp.gov.in पर राशन कार्ड से स्वयं अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता पारदर्शिता पोर्टल https://epds.hp.gov.in पर जा कर "Update Mobile Number" विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों का आधार कार्ड दर्ज करने के उपरान्त अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।

उन्होंने समस्त राशन कार्ड उपभोक्ताओं से नजदीकी उचित मूल्य की दुकान एवं लोक मित्र केंद्र या एंडरॉयड मोबाइल एप्लिकेशन eKYc PDS HP के द्वारा eKYc प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा करने का आग्रह किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस भर्ती की आवेदन तिथि 12 नवम्बर तक बढ़ाई

मुख्यमंत्री ने युवाओं के हित में लिया फैसला

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर आयोग द्वारा की जा रही पुलिस भर्ती की आवेदन तिथि 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 12 नवम्बर, 2024 की गई है। मुख्यमंत्री ने यह फैसला पुलिस भर्ती में युवाओं को आवेदन के लिए और अधिक समय देने के दृष्टिगत लिया है और इस निर्णय से हजारों युवा लाभान्वित होंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने लगभग 20 माह के कार्यकाल में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए हैं और इस छोटी सी अवधि में 31 हजार से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित किए गए हैं। इसी कड़ी में आयोग द्वारा प्रदेश पुलिस में 1088 पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं।

राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया है जिसके दृष्टिगत इन 1088 पदों में से महिला कांस्टेबल के लिए 380 पद आरक्षित किए गए हैं। शेष 708 पदों पर पुरुष कांस्टेबल की भर्ती की जा रही है।

इसके अलावा राज्य सरकार ने कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की है। इस आयु सीमा में छूट के निर्णय से अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल की भर्ती के लिए पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन्न समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला किन्नौर में चार दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव किन्नौर के पारम्परिक संगीत,

नृत्य और कला शैलियों का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री ने किन्नौर की अनूठी परम्पराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए वहां के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव न केवल समुदाय को एकजुट करते हैं बल्कि लोगों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रू-ब-रू भी करवाते हैं।

प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध संस्कृति को संजोकर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास और यहां के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं और जल्द ही किन्नौर में एक हैलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, यहां के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए 28 करोड़ रुपये की लागत से खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किन्नौर जिला के टापरी में जियोथर्मल तकनीक से विश्व का पहला नियंत्रित वातावरण भंडारण सीए स्टोर का निर्माण कर रही है। इसके लिए आईसलैंड व हिमाचल सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इससे क्षेत्र बागवान लाभान्वित होंगे और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत बागवानों से प्रति किलो के हिसाब से सेब की खरीद की जा रही है, जो सरकार की सुशासन प्रणाली से ही संभव हो पाया है।

उन्होंने कहा कि किन्नौर के निगुलसरी में बारिश के कारण अधिकतम समय सड़क मार्ग अवरूद्ध रहता है। प्रदेश सरकार ने रिकांगपिओं के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ताकि क्षेत्रवासियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिले के निर्धन एवं भूमिहीन लोगों को भू-पट्टे प्रदान कर उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय किन्नौर उत्सव के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगितों के विजेताओं को सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शिनियों का अवलोकन भी किया और सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया।

किन्नौर को 30.70 करोड़ रुपये की दी सौगात

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला किन्नौर प्रवास के दौरान 30.70 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में 2.69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ई.वी.एम. वेयर हाऊस, 94.95 लाख रुपये से निर्मित कोषागार कार्यालय के कर्मचारियों के छः टाइप-2 आवासों तथा 6.85 करोड़ रुपये से निर्मित 250 मीट्रिक टन क्षमता के सी.ए. स्टोर का लोकार्पण किया।

उन्होंने ग्राम पंचायत सांगला में रोखटी नाला में 1.35 करोड़ रुपये, निचार तहसील की ग्राम पंचायत कटगांव के शांगो गांव में 6.95 करोड़ रुपये तथा ग्राम पंचायत सापनी में 5.13 करोड़ रुपये के बाढ़ नियंत्रण कार्यों, तहसील कल्पा में कटौंगटी खड्ड के 1.88 करोड़ रुपये के तटीकरण एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों तथा ग्राम पंचायत रकछम में गांव रकछम की बस्पा नदी पर 94.38 लाख रुपये से बाढ़ नियंत्रण कार्यों के शिलान्यास किए। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने गांव नमज्ञा में 3.96 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह पुस्तकालय विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था

की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की लगभग 2,500 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें ऑफलाइन माध्यम से पहली से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी और सीबीएसई की पुस्तकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कॉलेज के पाठयक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न शैक्षिक पुस्तकें डिजिटल लाइब्रेरी में पाठकों के लिए उपलब्ध होंगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 'डिजिटल लाइब्रेरी पाठकों को टचस्क्रीन डिवाइस, सर्वर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध करवाएगी। इस लाइब्रेरी को एक स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली आरएफआईडी तकनीक से सुव्यवस्थित किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए उन्हें आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे लाइब्रेरी में प्रवेश करने के लिए स्कैन करना आवश्यक होगा।'

विद्यार्थियों के लिए जिला पुस्तकालय में एक बड़ा रीडिंग हॉल, एक ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर टैबलेट, उपयुक्त फर्नीचर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत पुस्तकालय में सीसीटीवी प्रणाली को स्थापित किया गया है।

डिजिटल लाइब्रेरी में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने डिजिटल तकनीक को एकीकृत करने और बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में तकनीकी उपयोग के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने बताया कि इस तरह के सुधारों से उनके जानने और सीखने के अनुभव में वृद्धि हो रही है। तकनीक को समायोजित करने से अब पढ़ाई और अधिक रूचिकर बन गई है। विद्यार्थियों में पढ़ने और सीखने की आदत को प्रोत्साहन प्रदान करने की प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से उनका ज्ञानवर्द्धन होगा जिसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

मुख्यमंत्री ने 1.67 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बिलासपुर के नए भवन का भी उद्घाटन किया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और तिलक राज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में परिवार के साथ दिवाली मनाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिवाली के शुभ अवसर पर अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में

अपने परिवार के साथ विधिवत पूर्जा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की।

प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व लोगों के जीवन में रोशनी, एकता, समृद्धि और खुशियां लेकर आता है।

उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से एकता, सहभागिता की भावना को अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि यह भावनाएं समाज, राज्य एवं देश का विकास और कल्याण सुनिश्चित करती हैं।

इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और प्रदेश की शांति और समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दीं कई सौगातें

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग के नए उप-मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नए उप-मंडल कार्यालय के खुलने से डढवाल क्षेत्र में सड़कों के रख-रखाव में सुधार होगा जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। अब तक बड़सर

उपमंडल पर 600 किमी सड़कों के रख-रखाव का कार्यभार था लेकिन अब बिझड़ी में नया कार्यालय खुलने से लोक निर्माण विभाग ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्य करने में सक्षम होगा।

मुख्यमंत्री ने 3.19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 12 किलोमीटर लंबी बड़सर-शाहतलाई सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष शाहतलाई, दियोटसिद्ध और अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस सड़क मार्ग से सुगम आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 24 किमी लंबे सलौणी-दियोटसिद्ध सड़क मार्ग के उन्नयन/विस्तारीकरण की आधारशिला भी रखी। इस कार्य पर 26.32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह सड़क मार्ग अभी 3.2 मीटर चौड़ा है जिसका 5.5 मीटर तक विस्तारीकरण किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू कां ने नादौन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने शिमला में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने बजट तैयार करने के लिए सभी अनिवार्य औपचारिकताओं को समयबद्ध पूरा करने के दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दस में से पांच गारंटियों को पहले ही पूरा कर चुकी है और अन्य गारंटियों को पूरा करने के लिए भी तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता प्रतिपक्ष आये दिन बेतुकी और आधारहीन ब्यानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में अंतर्कलह का बोलबाला है और पार्टी पूरी तरह कई टुकड़ों में बंट चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा नेता गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने एक माह में अपने कर्मचारियों को दो बार वेतन अदा किया है लेकिन यह जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं दी गई। प्रदेश सरकार ने अक्तूबर माह का वेतन चार दिन पहले अदा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 22 माह के कार्यकाल में कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है।

मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल प्रदेश बने इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर आगे बढ़ रही है।

मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है।

......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

मुफ्ती के हमाम में सारे दल बराबर के नंगे है

किसी भी राजनीतिक दल और उसके नेतृत्व का व्यवहारिक आकलन तभी संभव होगा जब वह सत्ता में आयेगा। सत्तारूढ़ दल पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रमाणिकता का पता भी तब चलेगा जब वह किसी निष्पक्ष जांच में सत्यापित हो जाये। इन मानकों पर यदि 2014 के बाद की राजनीति पर नजर डालें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। 2014 के पहले अन्ना हजारे और रामदेव के आन्दोलन में भ्रष्टाचार और काले धन केंद्रीय बिन्दु थे। इसी काले धन के आंकड़ों पर हर नागरिक के खाते में पन्द्रह-पन्द्रह लाख आने का वायदा किया गया था। 2जी स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घपला होने का आरोप देश के महालेखाकार विनोद राय की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की भ्रष्टाचार की जांच के लिये लोकपाल नियुक्त किये जाने की मांग उठी। इस मांग पर डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ही लोकपाल विधेयक पारित कर गई थी। 2014 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो गया। 1,76,000 करोड़ के 2 जी घोटाले की जांच में विनोद राय ने ही यह कह दिया कि उन्हें गणना में गलती लगी थी और कोई घपला नहीं हुआ है। लोकपाल नियुक्त है लेकिन कितने मामले इसके पास पहुंचे और प्रमाणित हुये इसकी कोई रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आयी। कितना काला धन विदेशों से वापस लाया जा सका है इसका भी कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। बल्कि विदेशों में भारत का काला धन कितना बढ़ गया है इसकी रिपोर्ट जरूर आयी है। जो लोग बैंकों के साथ धोखाधड़ी करके विदेश चले गये हैं उनमें से कोई भी भारत वापस नहीं लाया जा सका। देश में दो बार नोटबन्दी हो गयी है लेकिन इससे क्या हासिल हुआ है इस पर कोई रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हो सकी है। भारत विश्व गुरु हो रहा है और आज भारत के रिश्ते कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन के साथ किस मोड़ पर खड़े हैं यह सबके सामने है।

आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। 140 करोड़ के देश में यदि आज भी 80 करोड़ सरकार के राशन पर आश्रित हैं तो इसे विकास का कौन सा मानक माना जाये। पिछले एक दशक में कितने सार्वजनिक उपक्रम प्राइवेट सैक्टर के हवाले किये जा चुके हैं यह सबके सामने है। लाखों करोड़ का ऋण बड़े औद्योगिक घरानों का माफ किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत बांटा गया कितना पैसा वापस नहीं आया है इसका कोई रिकार्ड जारी नहीं हुआ है। इस परिदृश्य में राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिये मतदाताओं को इतनी मुफ्ती योजनाओं की गारंटीयां देना शुरू कर दिया है कि इससे हर राज्य का वित्तीय गणित गड़बड़ा गया है। आज हर राज्य का कर्जभार जीडीपी अनुपात की प्रतिशतता से कहीं आगे बढ़ गया है। क्योंकि मुफ्ती की गारंटीयों को पूरा करने के लिए कर्ज की अतिरिक्त और कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस बढ़ते कर्जभार का सबसे ज्यादा प्रभाव सरकारी रोजगार पर पड़ रहा है क्योंकि सरकारों के पास सबसे ज्यादा खर्च सरकारी कर्मचारी के वेतन भतों और पैन्शन पर आता है इसलिए इस प्रतिबद्ध खर्चे से बचने के लिये अब सरकारें आउटसोर्स के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करने के विकल्प पर चल पड़ी है। केन्द्र से लेकर राज्यों तक की सरकारों में करोड़ों पद खाली है जिन्हें भरा नहीं जा रहा हिमाचल जैसे राज्य में ही एक लाख से ज्यादा पद खाली है।

इस वस्तुस्थिति में देखा जाये तो यही सामने आता है की राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिये मतदाताओं को किसी भी तरह के चुनावी प्रलोभन देने में किसी भी हद तक जा सकते हैं यह प्रलोभन देते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। इसी से राज्यों का वित्तीय संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में इन मुफ्ती की घोषणाओं पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आरबीआई ऐसी घोषणाओं पर राज्यों और राजनीतिक दलों को सचेत कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर याचिकायें आ चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय फ्रीबीज के खिलाफ चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर यह निर्देश दे चुका है कि ऐसी घोषणाओं पर रोक लगाने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देशित करें। परन्तु चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार दोनों ही इस मुद्दे पर व्यवहारिक रूप से गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि केन्द्र में सतारूढ़ भाजपा और उसके शासित राज्यों में चुनावी घोषणा पर नजर डाली जाये तो भाजपा द्वारा घोषित मुफ्ती योजनाओं का आकार अन्य दलों की घोषणाओं से कहीं ज्यादा बढ़ जायेगा। शायद इसलिये केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस का जवाब दायर नहीं कर पा रही है। इसलिये मुफ्ती की घोषणाओं का राज्य के वित्तीय संसाधनों पर कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा इसका आकलन और संज्ञान अब मतदाता को ही लेना पड़ेगा। मुफ्ती की घोषणाओं को पूरा करने के लिये सरकार न तो कर्ज ले और न ही राज्यों के लोगों पर करो का बोझ डालेगी यह शर्त राजनीतिक दलों पर होना आवश्यक है।

कारीगरों का सम्मान: पीएम विश्वकर्मा योजना

77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत भर के कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल का अनावरण किया: पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के दौरान द्वारका, नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में लॉन्च की गई यह योजना, पारंपरिक शिल्प कौशल का समर्थन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 16 अगस्त, 2023 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य विभिन्न पारंपरिक शिल्पों में कुशल व्यक्तियों का उत्थान करना है, जिससे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके।

यह योजना अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में लगे कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को लक्षित करती है, जहाँ लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, बढ़ई जैसे कारीगर अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं। इन कारीगरों को विश्वकर्मा कहा जाता है। कारीगरों के ये कौशल अक्सर पीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं, गुरु-शिष्य प्रारूप का पालन करते हुए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देते हैं, जो सदियों पुरानी परंपराओं की निरंतरता को बढ़ावा देता है। कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार पहुंच को बढ़ाकर, पीएम विश्वकर्मा योजना इन कुशल व्यक्तियों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, दोनों में एकीकृत करना चाहती है।

अपनी शुरुआत के बाद से, इस योजना के प्रति कारीगरों ने उल्लेखनीय रुचि दिखायी है, जिसके तहत 25.8 मिलियन आवेदन जमा किए गए हैं। इनमें से, 2.37 मिलियन आवेदकों ने तीन-चरण की सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है।

इसके अलावा, लगभग 1 मिलियन पंजीकृत कारीगरों को ई-वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपये तक के टूलकिट प्रोत्साहन से लाभ हुआ है, जिससे वे अपने शिल्प कौशल में वृद्धि करने वाले आधुनिक उपकरण प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करने और देश की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को मूर्त रूप देने वाले कारीगरों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के संकल्प का प्रमाण है।

योजना की मुख्य बातें

➢ पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, जिसका वित्तीय परिव्यय पांच साल (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपये है।

➢ विश्वकर्माओं को बायोमेट्रिक-आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करते हुए सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकृत किया जाता है।

➢ कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और एक आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है।

➢ उन्हें 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किस्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किस्त) तक का गिरवी-मुक्त ऋण समर्थन प्राप्त होता है। भारत सरकार 8% की सीमा तक ब्याज अनुदान देती है और यह धनराशि बैंकों को अग्रिम रूप से प्रदान की जाती है।

➢ यह योजना, शिल्पकारों को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण, 15,000 रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन तथा डिजिटल लेनदेन और विपणन सहायता के लिए प्रोत्साहन सहित कौशल उन्नयन के तरीके प्रदान करती है।

मुख्य लाभ

औजार सुविधाओं तक बेहतर पहुँच: औजार संसाधनों तक एमएसएमई की पहुँच में सुधार, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है।

उद्योग-अनुरूप जनशक्ति: प्रतिभागियों को उद्योग मानकों को पूरा करने वाले कौशल देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

प्रक्रिया और उत्पाद विकास के लिए समर्थन: योजना प्रतिस्पर्धी बढ़ाने के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों के भीतर विकास पहलों को सुविधाजनक बनाती है।

परामर्श और नौकरी से जुड़ी सेवाएँ: योजना विभिन्न उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप परामर्श और नौकरी से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करती है।

कौन आवेदन कर सकता है

औद्योगिक इकाइयाँ: विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए लक्षित।

प्रशिक्षण कार्यक्रम पात्रता: स्कूल छोड़ने वालों से लेकर एम.टेक डिग्री धारियों तक के लिए खुला है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, अपने हाथों और औजारों से अथक परिश्रम करने वाले भारत के विश्वकर्माओं के उत्थान, उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास है।

यह योजना भारत भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी और सरकार के गरीबी उन्मूलन प्रयासों में मदद करेगी।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 25 पारंपरिक कार्य (ट्रेड) शामिल हैं

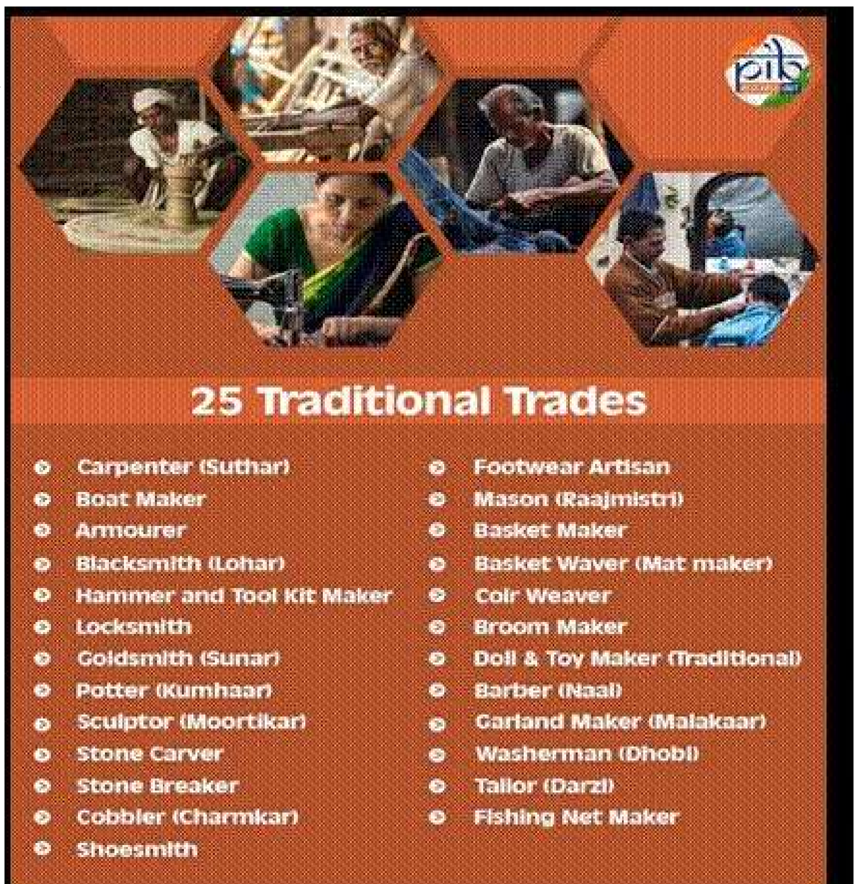

प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से किसानों के जीवन में आ रही सम्पन्नता

देश भर में ग्राम पंचायतों को सबल बनाने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

मानकीकृत मानदेय, स्मार्ट कक्षाओं में प्रशिक्षण, जमीनी स्तर पर सेवा सुविधाओं में सुधार के लिए नए पंचायत भवन

शिमला। देश भर में जमीनी स्तर पर शासन की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय एमओपीआर के सचिव विवेक भारद्वाज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित संशोधित योजना की केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति सीईसी ने अपनी 8वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आरजीएसए के तहत मानकीकृत मानदेय को अपनाना, पंचायत अधिकारियों का दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण, स्मार्ट कक्षाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में ग्राम पंचायत बुनियादी ढांचे में निवेश सम्बंधी प्रमुख निर्णय लिए गये।

आरजीएसए के अंतर्गत मानकीकृत मानदेय प्रणाली को अपनाना

सीईसी ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मास्टर प्रशिक्षकों, अतिथि संकायों और विशेष संसाधन के तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मानदेय दरों के मानकीकरण को मंजूरी दी। यह निर्णय न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करता है और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों की उपलब्धता को बढ़ावा देता है, जो जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण कार्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यह निर्णय पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई में प्रशिक्षण स्थिरता और क्षमता निर्माण के लिए मानदेय की असमानताओं को दूर करके एक नया मानदंड स्थापित करता है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से लेकर सिक्किम और गोवा जैसे छोटे राज्यों तक, पूरे देश में प्रशिक्षण कार्य में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही अपनी प्रशिक्षण पहलों को विस्तार दे रहें बिहार, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश उच्च शिक्षा के लिए दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पंचायत अधिकारियों को प्रायोजित करेंगे

आरजीएसए के राज्य घटक के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के लिए एक वर्ष तक की अवधि वाले दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दे दी गई है। इस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों को उत्कृष्ट संस्थानों से उन्नत, क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण मिले, जो जमीनी स्तर पर बेहतर सेवा सुविधाओं के लिए उनके कौशल को उन्नत करेगा। यह विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को मजबूत करने और कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करने के आरजीएसए के उद्देश्य के अनुरूप है। यह ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन में भूमिका निभा रहें अधिकारियों की समग्र योग्यता को बढ़ावा देगा, जिससे जमीनी स्तर पर योजना में सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप कुछ वर्षों की अवधि में पीआरआई में पूंजी निर्माण में सहायक व्यापक तौर पर श्रम कौशल में दक्ष कामगारों की संख्या में वृद्धि होगी।

यह निर्णय सभी सहभागी राज्यों में पीआरआई कार्यकर्ताओं के गहन कौशल में वृद्धि की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानिक नियोजन, संसाधन जुटाना और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल करके केरल के तटीय क्षेत्रों से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों तक विविध भौगोलिक संदर्भों में ग्रामीण विकास के लिए अधिकारियों आवश्यक व्यापक ज्ञान बढ़ाना है। इस निर्णय से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ होगा क्योंकि अब उत्तर पूर्व नई और पहाड़ी राज्य उच्च शिक्षा के लिए 10-10 उम्मीदवारों को प्रायोजित कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और गोवा अपने यहां से 5 आवेदकों को प्रायोजित कर सकते हैं जबकि अन्य राज्य 20 उम्मीदवारों को प्रायोजित कर सकते हैं।

पंचायती बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए, सीईसी ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों में सामान्य सेवा केंद्र सीएससी के साथ 3,301 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दी और ग्राम पंचायतों के लिए 22,164 कंप्यूटर स्वीकृत किए है। यह निर्णय इन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली को बढ़ावा देता है क्योंकि यह सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रशासनिक कामकाज और डिजिटल शासन को सक्षम किया जा सकता है। समर्पित भवनों और कंप्यूटर उपकरणों के प्रावधान से रिकॉर्ड को कुशल तरीके से संभाल कर रखने और ई-गवर्नेंस की सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय प्रशासन के संचालन और सेवा सुविधाओं में काफी वृद्धि होगी।

पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्मार्ट कक्षाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा

देश भर में राज्य और जिला स्तर पर पंचायत संसाधन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए, 25 राज्यों में राज्य पंचायत संसाधन केंद्रों एसपीआरसी के साथ-साथ 395 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केंद्रों डीपीआरसी में स्थित कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को नवीनतम तकनीक के अधिक संख्या में कंप्यूटरों के साथ आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इन एसपीआरसी और डीपीआरसी में तकनीकी शैक्षिक सहायक उपकरण स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्य और जिला पंचायत संसाधन केंद्रों एसपीआरसी/डीपीआरसी को अपग्रेड करने का यह निर्णय, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाएगा और एक अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करेगा। प्रोजेक्टर, एलसीडी, इंटरैक्टिव पैनल और पीए सिस्टम सहित डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करके, प्रशिक्षण केंद्र उच्च गुणवत्ता वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे।

पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के सशक्त गांवों के पंचायती बुनियादी ढांचे में निवेश

पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। पिछले वर्षों में मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में निवासियों की सुविधा के लिए पंचायत भवनों के निर्माण के साथ-साथ सामान्य सेवा केंद्र की स्थापना का भी समर्थन किया है। जम्मू-कश्मीर में मंत्रालय ने 2024-25 के दौरान 970 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और 1606 सामान्य सेवा केंद्रों की सह-स्थापना का समर्थन किया है।

इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश में 400 पंचायत भवन-सह-सामान्य सेवा केन्द्रों के निर्माण का निर्णय लिया गया है । यह पिछले दिनों पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 939 ग्राम पंचायत भवनों के लिए सीएससी के साथ किए गए सहयोग का ही एक हिस्सा है। इसी तरह, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लिए पंचायत बुनियादी ढांचे का समर्थन किया गया है। कुल मिलाकर, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 1633 ग्राम पंचायत भवन और 514 सीएससी को मंजूरी दी गई है।

इन पहलों का उद्देश्य सशक्त गांवों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और जमीनी स्तर पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है।

ग्रामीण भारत में 4,740 डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे

ग्रामीण भारत में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पीलीभीत और गोरखपुर से डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र डीआईसीएससी परियोजना शुरू कर रहा है । इस पहल से 10 जिलों की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक म डल डीआईसीएससी केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे देश भर में कुल 4,740 केंद्र बनेंगे। आधार पंजीकरण, बैंकिंग, वित्तीय नियोजन, टेली-लॉ, टेलीमेडिसिन, शिक्षा और ई-कॉमर्स सहायता सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगे।

उच्च गति इंटरनेट से विकास को बढ़ावा मिलेगा

प्रत्येक सीएससी को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले सेवा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य ग्राम स्तरीय उद्यमियों वीएलई को सशक्त बनाना,

CSC™
e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED

भारत भर में डीआईसीएससी

विशेष रूप से, पीलीभीत में 720 डीआईसीएससी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जबकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 1,273 केंद्र होंगे। अन्य स्थानों पर महाराष्ट्र में पुराना औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर में 870 केंद्र, हिमाचल प्रदेश के चंबा में 309, तेलंगाना के खम्मम में 589, गुजरात के गांधीनगर में 288, मिजोरम के ममित में 100, राजस्थान के जोधपुर में 415, लद्दाख के लेह में 95 और पुदुचेरी में 81 डीआईसीएससी केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों के कार्यान्वयन और केंद्रीकृत तकनीकी निगरानी का प्रबंधन सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

इकतीस करोड़ साठ लाख अठासी हजार (31.6088) करोड़ के बजट वाली यह परियोजना शुरुआत में छः महीने तक चलेगी और इस अवधि को नौ महीने तक बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं के साथ-साथ आवश्यक ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने वाला एक एकीकृत मंच बनाना है। पीलीभीत में सीएससी केंद्र स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह पहल केंद्रीकृत तकनीकी निगरानी के माध्यम से पारदर्शी और टिकाऊ सेवा वितरण भी सुनिश्चित करेगी।

इसके अतिरिक्त, सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने और दूरदराज के क्षेत्रों में सीधे आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए जीपीएस-तकनीक सक्षम मोबाइल वैन तैनात की जाएंगी। इस व्यापक दृष्टिकोण से पीलीभीत और गोरखपुर दोनों में डिजिटल साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि और सेवाओं तक पहुँच में सुधार होने की उम्मीद है।

डीआईसीएससी परियोजना स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं प्रदान करके इन क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल कार्यप्रणाली को लागू करके आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर, पीलीभीत और गोरखपुर की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना है और वहां व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था में समन्वय करना है।

प्रदेश सरकार वंचित वर्गों का कर रही कल्याण सुनिश्चित

सामाजिक सुरक्षा पहल से आठ लाख लोगों के जीवन में आई खुशहाली

शिमला। सामाजिक सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार हिमाचल का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। वंचित वर्गों के कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रदेश सरकार के समर्पित प्रयासों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 1,537.67 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन और विशेष रूप से सक्षम लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के कल्याण को केन्द्र में रखकर 2,483.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रदेश सरकार की इस नवोन्मेषी पहल से वंचित वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान में प्रदेश में आठ लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने विधवाओं, एकल महिलाओं और दिव्यांगजनों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को कम करने के दृष्टिगत कुछ पात्रता मापदंडों को लचीला बनाया है, जिसके फलस्वरूप लगभग 76,000 नए लाभार्थी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को विस्तार प्रदान कर वंचित वर्गों तक इसके लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का यह प्रयास समावेशी समाज की परिकल्पना को साकार करता है।

समाज के कमजोर वर्गों के सपनों के घर को हकीकत में बदलते हुए प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को प्रति परिवार 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल कौशल से लैस करने और उन्हें आधुनिक तकनीक में सशक्त करने के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। समाज में सद्भाव की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अंतर्जातीय विवाह के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वृद्धजनों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 11 वृद्धाश्रम, 22 डे केयर सेंटर और सात वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से उन्हें बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आश्रमों में रह रहे आवासियों को उत्सव भत्ता प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे जीवन की खुशियों को अनुभव कर सकें। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 'असीम' नामक एक दूरगामी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को 625 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक की मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है, ताकि वे अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने साकार कर सकें।

दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 25 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा, दिव्यांग लोगों की देखभाल और सहायता करने वाली संस्थाएं चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को भी अनुदान सहायता का प्रावधान किया जा रहा है।

कांगड़ा जिला के लुथान का आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर 400 से अधिक बुजुर्ग और निराश्रितों को आवासीय सुविधा प्रदान करेगा। यह परिसर अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित किए जाएंगे और यहां रहने वाले आवासीयों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

प्रदेश सरकार वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में समग्र प्रयास कर रही हैं। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप ये वर्ग समाज की मुख्य धारा में जुड़कर प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के टूटीकंडी बाल आश्रम और मशोबरा स्थित बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली मनाई और उन्हें त्यौहार की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बच्चों के साथ लक्ष्मी पूजा की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिठाई, आतिशबाजी और अन्य उपहार भेंट करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्रम के बच्चों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन बच्चों की शिक्षा के अलावा भ्रमण का खर्च भी उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इन बच्चों को शैक्षिक यात्रा और एक्पोजर विजिट के लिए गोवा और अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाने की योजना है और भ्रमण के दौरान इन बच्चों के रहने-खाने और यात्रा का खर्च भी प्रदेश सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अनाथ और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दिया गया है और सरकार इन बच्चों का परिवार के सदस्यों के रूप में ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि सभी अनाथ बच्चे राज्य की जिम्मेदारी हैं और उचित देखभाल इन बच्चों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इन बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा देने और इनके अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा, सरकार इन बच्चों को कोचिंग के लिए 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन शिमला को मशोबरा में बालिका आश्रम में एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आश्रम के बच्चों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने मशोबरा में नारी सेवा निकेतन का भी दौरा किया और आश्रितों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उपहार वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने कल्पा में बालिका आश्रम का दौरा किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला किन्नौर के कल्पा में बालिका आश्रम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अनाथ और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दिया गया है और सरकार इन बच्चों का परिवार के सदस्यों के रूप में ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि सभी अनाथ बच्चे राज्य की जिम्मेदारी हैं और उचित देखभाल इन बच्चों का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश इन बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा देने और इनके अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने बालिका आश्रम की बालिकाओं से बातचीत की और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इन बच्चियों की देखभाल और शिक्षा के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने आश्रम की बालिकाओं को जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और निरन्तर प्रयास करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्त किन्नौर को बालिका आश्रम का समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों की सभी समस्याओं का समय पर निवारण हो सके।

मुख्यमंत्री ने आश्रम की प्रत्येक बालिका को दिवाली उपहार के रूप में 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने बच्चियों को ट्रैक सूट भी भेंट किए। इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने कल्पा के बौद्ध मन्दिर में शीश नवाया।

राष्ट्रीय संकल्प दिवस पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राष्ट्रीय संकल्प दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय संकल्प दिवस पर शपथ भी दिलाई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय संकल्प दिवस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थीं और उन्होंने आतंकवाद का मजबूती से सामना किया। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान तथा कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की।

मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें भी याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है तथा उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई।

इस दौरान सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने देश भक्ति और भजन गीतों की प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक शिमला शहरी हरीश जनारथा, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, उपमहापौर उमा कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, पार्षदगण, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय से कालका-शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय रेल मंत्रालय से यूनेस्को विश्व धरोहर कालका-शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय को इस ऐतिहासिक रेल लाइन को ग्रीन एनर्जी संचालित रूट में बदलने पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अनेक पहल की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को प्रमाणित ग्रीन एनर्जी स्टेट में बदलने के लिए छः सूत्रीय रणनीति के तहत कार्य कर रही है। सरकार की यह पहल भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार की रणनीतिक पहल के तहत सतत् एवं अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा प्रदान कर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश अपनी वर्तमान 1,500 मिलियन यूनिट थर्मल पावर खपत को हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय स्रोतों से बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में राज्य 13,500 मिलियन यूनिट बिजली की खपत करता है जिसकी एक बड़ी आपूर्ति पहले से ही नवीकरणीय स्रोतों से पूरी होती है। बिजली वितरण तंत्र में 90 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा खपत प्राप्त करने से हिमाचल को देश के पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा राज्य के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है और एक वर्ष के भीतर इस लक्ष्य को हासिल करने की संभावना है। इससे प्रदेश के उद्योगों को 'इको मार्क' के लिए आवेदन करने की भी अनुमति भी मिल सकेगी, जिससे उनके उत्पादों की मूल्य में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत अगले चार से पांच वर्षों में 2,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दो वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना हो गया है, जो प्रदेश सरकार की स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की विकेन्द्रिकरण पहल के तहत 'ग्रीन पंचायत' योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर 500 किलोवाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके तहत बिजली की बिक्री से होने वाली आय का उपयोग पर्यावरण अनुकूल और सत्त विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य 'ग्रीन हाइड्रोजन' के उत्पादन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल के सहयोग से इस सुविधा का काम चल रहा है और इस तरह की अन्य सुविधाओं के लिए निजी निवेशकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम की 3,200 बसों के बेड़े में से 1,500 बसों को आगामी दो से तीन वर्षों में इलेक्ट्रिक बसों से बदला जा रहा है। सरकार के विभिन्न विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों के बेड़े को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है। इसके अतिरिक्त, छह प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को ई वाहनों के संचालन के लिए ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत, बेरोजगार युवाओं को इलैक्ट्रिक टैक्सी और बसें खरीदने के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है, इससे सरकारी सेवाओं में पर्यावरण अनुकूल वाहनों का संचालन सुनिश्चित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नए उद्योगों या मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए सख्त मानक संचालन प्रणाली को लागू कर सभी प्रस्तावों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है।

बनखंडी में स्थापित होगा भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणित चिड़ियाघर:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में बनखंडी में बनने वाला 'दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान' भारत का पहला चिड़ियाघर होगा जिसे सतत् और पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) से प्रमाणन प्राप्त होगा। इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर आईजीबीसी के साथ पंजीकृत किया गया है। प्राणी उद्यान में पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना करते हुए भवन और परिदृष्य प्रमाणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास कर रही हैं और आईजीबीसी प्रमाणन प्रक्रिया प्रदेश सरकार की इस प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह प्रमाणन पर्यटन और बुनियादी अधोसंरचना के विकास में पर्यावरण संरक्षण को एकीकृत करने की राज्य सरकार की प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है। दुर्गेश अरण्य पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने के साथ-साथ यह पार्क संरक्षण और नवाचार की बेजोड़ कृति साबित होगा। सुक्खू ने कहा कि 'दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान' परियोजना का पहला चरण लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से 25 हेक्टेयर भूमि में स्थापित किया जा रहा है। जिसके वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 619 करोड़ रुपये के लागत से निर्मित होने वाला प्राणी उद्यान पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा और इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पहले चरण के अंतर्गत जैव विविधता सुनिश्चित करते हुए 34 पशुओं के बेड़े बनाए जाएंगे जिसके लिए प्रदेश सरकार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके तहत एशियाई शेर, हॉग डियर, मॉनिटर छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल और विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों सहित 73 प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाएगा। चिड़ियाघर में एक नॉक्टर्नल हाउस बनाया जाएगा जिसमें बिल्लियों की प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, चिड़ियाघर में एक वेटलैंड एवियरी में स्वदेशी प्रजातियों के पक्षियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा में स्थापित हो रहे दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान से क्षेत्र में पर्यटन को नए पंख लगेंगे और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जिला कांगड़ा की अद्वितीय सुंदरता और प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित की जा रही पर्यावरणीय अनुकूल अधोसंरचना से कांगड़ा जिला पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन कर उभर रहा है। यह नवीन प्रयास राज्य सरकार की इको-टूरिज्म और सतत् विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जिससे कांगड़ा राज्य की 'पर्यटन राजधानी' के रूप में स्थापित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के मंडी-भराड़ी स्थित गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारम्भ किया। क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नए आयाम प्रदान करते हुए यहां क्रूज, शिकारा राइड, हाउसबोट, हाई-टेक मोटरबोट, जेट स्कीज़ और वाटर स्कूटर गतिविधियों को शुरू किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यटन के साथ-साथ इस नवीन पहल से स्थानीय व्यवसायों, विशेष रूप से महिला एवं छोटे उद्यमियों को स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए नया बाजार उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आर्थिक सुदृढ़ होगी।

बिलासपुर को पर्यटक स्थल के रूप में उभारने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक, ग्रामीण और इको-पर्यटन के साथ-साथ जल आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित कर बिलासपुर को केरल और गोवा की तर्ज पर आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला की नैसर्गिक सुन्दरता, सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक गतिविधियों को प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर बिलासपुर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा के प्रदेश सरकार के बहुआयामी प्रयासों के फलस्वरूप क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिला प्रशासन को कोल डैम जलाशय पर क्रूज और शिकारा संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के तहत बिलासपुर जिले के हरनोड़ा से शिमला जिले के तत्तापानी तक 30 किलोमीटर का एक सुंदर क्रूज मार्ग विकसित किया जाएगा। यह जल मार्ग पर्यटकों को एक अविस्मरणीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। पर्यटक कोल डैम के माध्यम से शिमला की ओर एक यादगार क्रूज की सवारी का आनंद ले सकेंगे।

प्रदेश में पर्यटन की नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने जेट स्की पर एक रोमांचक सवारी और क्रूज की यात्रा का आंनद लिया। मुख्यमंत्री हिमाचल को देश के पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।

पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान सरकार के दो साल का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही बिलासपुर में क्रूज और अन्य जल क्रीड़ा संबंधी नवीन गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र का प्रमुखता से क्षेत्र का विकास कर रही है और हरित उद्योगों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचूर मात्र में उपलब्ध हैं और प्रदेश में जल क्रीड़ा गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार की दूरगामी सोच और प्रतिबद्धता के फलस्वरूप दो वर्ष के भीतर ही बिलासपुर में क्रूज, जेट स्की और शिकारों का सफल संचालन संभव हो पाया है।

मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शीघ्र होगी आरम्भः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' शुरू करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य दो विशिष्ट आयु समूहों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांग माता-पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विधवा और परित्यक्त महिलाओं को अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये महिलाएं विशेष रूप से कमजोर हैं और उन्हें खुद का अस्तित्व बनाए रखने व अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नैतिक और वित्तीय सहायता की कमी है। इस योजना का उद्देश्य पारिवारिक स्तर पर बाल संरक्षण को सुदृढ़ कर बाल शोषण, तस्करी, बाल विवाह और मादक पदार्थों के दुरुपयोग जैसे अपराधों को रोकना है।

उन्होंने कहा कि विकलांगता, बेरोजगारी और गरीबी के दृष्टिगत 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' विकलांग माता-पिता के बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है।

सुक्खू ने कहा कि कमजोर परिवारों के लिए एक उचित माहौल को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक शिक्षा और देखभाल मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहले दिन से ही वंचित वर्गों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है और उनकी सहायता के लिए कई पहल शुरू की हैं। समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपनी शिकायतें और कठिनाइयां लेकर हमारे पास नहीं आ पाते हैं लेकिन एक संवेदनशील सरकार के रूप में हम हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बीड़-बिलिंग में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से बढ़ी हिमाचल की प्रतिष्ठाःआर.एस.बाली

शिमला/शैल। कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस.बाली ने किया। आठ दिवसीय प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव पशुपालन, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास किशोरी लाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर आर. एस. बाली ने कहा कि बीड़ बिलिंग दुनिया की सर्वोत्तम, विचित्र और लंबी साइट होने के कारण दुनिया भर के पैराग्लाइडरों का पसिंददा स्थान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में पैराग्लाइडिंग का विश्वस्तरीय आयोजन होना देश तथा प्रदेश के लिये गौरव की बात है और इसके आयोजन से दुनिया में हिमाचल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

उन्होंने कहा प्रदेश में साहसिक खेलों गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार इनके आयोजनों में हर सम्भव सहयोग कर आयोजकों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि बीड़ लैंडिंग साइट के लिये 60 लाख और अन्य सुविधाओं के लिये पर्यटन विभाग की ओर 7 लाख जारी किया गया है। इसके अलावा उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिये 35 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने खीर गंगा घाट पार्किंग में लिफ्ट लगाने की भी घोषणा की।

पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता की सफलता, सुरक्षा और सुखशांति से आयोजन के लिये शान्ति हवन का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति और परम्परा के अनुसार सभी की सुरक्षा के लिये आयोजित हवन में विदेशी पैराग्लाइडिंग प्रतिभागियों ने हवन में भाग लिया।

पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में 26 देशों के 94 पायलट भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 32 भारतीय प्रतिभागियों सहित 7 महिला प्रतिभागी भी शामिल हैं। आठ दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिये विशेष इंतजाम किये गये हैं। दो हेलीकॉप्टर, 7 स्वास्थ्य टीमें एम्बुलेंस सहित, 6-6 रेस्क्यू और रेट्रीवल टीमें तैनात की गई हैं। जो अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली से प्रशिक्षित लोगों की है।

पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों के मनोरंजन और विदेशी मेहमानों को समृद्ध भारतीय और देव भूमि हिमाचल की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिये 6 से 8 नवम्बर तक लैंडिंग साइट बीड़ में कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

मुख्यमंत्री ने की मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए निरन्तर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां और फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम शुरू किया है ताकि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने मन्त्रिमंडलीय सदस्यों को इस कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ शुरू हुई प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में सभी को समावेशी प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस प्रयास किए हैं जिसके धरातल पर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सुदृढ़ हो रही है।

उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों का समुचित व संतुलित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार राज्य के और प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनहित की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए विकासात्मक परियोजनाओं और योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करना नितांत आवश्यक है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित रहे।

धर्मशाला में आयोजित होगा संगीत महोत्सव

शिमला/शैल। टूमॉरो लैंड और सनबर्न जैसे अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों की तर्ज पर संगीत और संस्कृति का अनूठा संगम धर्मशाला पुलिस मैदान में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कपिल शर्मा शो जैसे प्रसिद्ध कार्यक्रम के निर्माता और महोत्सव के आयोजक तथा बीइंगयू के संस्थापक गुरजोत सिंह के साथ बैठक के दौरान इस आयोजन की विस्तृत जानकारी हासिल की। उन्होंने इस संगीत उत्सव के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के महोत्सवों से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी तथा होटल व्यवसायियों, रेस्तरां मालिकों और स्थानीय दुकानदारों सहित छोटे व्यवसायों को लाभ होगा।

गुरजोत सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रसिद्ध वार्नर म्यूजिक के सहयोग से वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसका उद्देश्य वैश्विक संगीत, स्थिरता, स्वास्थ्य और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मिलाकर विश्वस्तरीय प्रदर्शन, पर्यावरण कार्यशालाएं, रिट्रीट और सांस्कृतिक प्रदर्शनियां प्रस्तुत करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी गोकुल बुटेल भी उपस्थितथे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

25 हज़ार करोड़ का ऋण सुक्खू सरकार की अब तक की उपलब्धि:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पार्टी के घोषणा पत्र और अपने पार्टी के छोटे बड़े नेताओं के ब्यान फिर से सुनने चाहिए कि कैसी-कैसी गारंटियां कांग्रेस ने हिमाचल को दी थी। इसके साथ ही पार्टी मुख्यालय में पड़े वह फॉर्म भी देखने चाहिए कि किस तरह से युवाओं को स्टार्टअप फण्ड देने

और महिलाओं से सम्मान निधि के फॉर्म भरवाए गए थे। उसे देखकर शायद उन्हें याद आ जाए कि उन्हें किस लिए प्रदेश के लोगों ने बहुमत दिया था। यदि मुख्यमंत्री अब झूठ बोलना बंद कर दें तो प्रदेश पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अब तो उनके आलाकमान और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि झूठ बोलने के कारण और बड़े-बड़े चुनावी वायदे करने के कारण ही आज कांग्रेस की यह स्थिति हुई है। कांग्रेस के सभी सरकारों की इसी झूठ की वजह से किरकिरी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल में बोलें गए झूठ की वजह से आज कांग्रेस के किसी नेता और उनके ब्यान को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। गारंटियों को लेकर विधान सभा के भीतर भी उनके झूठ को हमने पूरे कागज-पत्र के साथ बेनकाब किया था और आगे भी करेंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल के बारे में जो कहा उसका एक-एक शब्द शत प्रतिशत सत्य है। हिमाचल पिछले महीनों से देशभर में चर्चा में है, जिसकी वजह से हिमाचल की छवि खराब हुई है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने पांच गारंटियां पूरी कर दी हैं। गारंटियों के हिसाब से उनकी सरकार बने दो साल हुए तो दो लाख लोगों को नौकरी देनी थी लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी। उल्टा डेढ़ लाख से ज्यादा पद खत्म कर दिए और 12 हज़ार से ज्यादा लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया। 18 से 60 साल की हर महिला को 1500 रुपए हर महीनें देने थे। कुल पात्र महिलाओं की संख्या 22 लाख के आस पास थी लेकिन लोक सभा चुनाव के ठीक पहले मात्र 26 हज़ार महिलाओं को एक किस्त देकर बैठ गये। इसके बाद से किसी को एक पैसा नहीं मिला है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी दी थी लेकिन पूर्व सरकार द्वारा दी गई 125 यूनिट बिजली की सुविधा भी खत्म कर दी और 300 यूनिट बिजली खर्च करने पर घरेलू उपभोक्ताओं से कमर्शियल रेट पर बिल लिए जा रहे हैं। गाय का दूध 80 और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदने की गारंटी दी थी। आज दूध की क्या कीमत हैं। हर विधान सभा के एक हज़ार युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फॉड बनाने की गारंटी दी थी। क्या हर विधान सभा के 10 युवाओं को भी स्टार्टअप का पैसा मिला? एक को भी नहीं मिला। इसके बाद भी यह कहना कि हमने गारंटी पूरी कर दी यह तो झूठ की हदें पार करने जैसा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन सब के बाद भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने पांच गारंटियां पूरी कर दी। इसका अर्थ यही है कि सरकार अब इन गारंटियों के मामले में कुछ नहीं करने वाली है। जो करना था वह कर चुकी है। इसलिए प्रदेश के लोग अब सरकार से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद न रखे। सुक्खू सरकार आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था पतन और प्रदेश के बंटाधार करने के लिए जानी जाएगी। आज प्रदेश की आर्थिक हालत की जिम्मेदार सुक्खू सरकार है, जिसने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दो साल से कम के कार्यकाल में ही 25 हज़ार करोड़ का ऋण ही सुक्खू सरकार की अब तक की उपलब्धि है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह उन्हें भी यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके झूठ की वजह से ही सरकार की किरकिरी हो रही है।

हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा ही धोखा:सुखराम चौधरी

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने जनता के लिए खरबों की सौगात दी पर

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने यह सब छीन ली। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए युवा आवेदन नहीं कर पा रहे थे। आवेदन के लिए 31 अक्तूबर अंतिम तिथि तय की गई थी। बताया जा रहा है कि पिछले पांच दिन से साइट में दिक्कत चल रही है। इससे आवेदन नहीं हो पाया। रोजाना युवा लोकमित्र केंद्रों और साइबर कैफे में आवेदन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन साइट नहीं चलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। बार-बार साइट हैंग होने से युवाओं को परेशानी आ रही थी। अब अगर सरकार 15 दिन बढ़ने की बात कर रही है तो उन्होंने प्रदेश के युवाओं पर कुछ एहसान नहीं किया वो उनका हक था।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के तहत बेरोजगारों को ई-टैक्सी परमिट देने की योजना बैंक ऋण की गारंटी के फेर में उलझ गई है। बैंक प्रबंधन बिना गारंटी ऋण देने को तैयार नहीं हैं और त्रिपक्षीय समझौता बनाने की मांग कर रहे हैं। योजना के तहत ई-टैक्सी परमिट के लिए एक साल पहले आवेदन कर चुके सैकड़ों युवाओं की परेशानी बढ़ गई है। योजना लागू होने पर बैंक प्रबंधन ऋण देने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन अब ऋण वापस करने की गारंटी मांग रहे हैं। बेरोजगार युवाओं ने हजारों रुपये चुका कर डीलरों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बुक करवाई हैं। युवाओं का कहना है कि ऋण की स्वीकृति न मिलने से गाड़ी की बुकिंग राशि जब्त हो सकती है। इतना ही नहीं बेरोजगार युवाओं से सिक्योरिटी के नाम पर जमीन के कागज मांगे जा रहे हैं हालांकि आवेदन के समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी। इस समय प्रदेश में युवाओं के साथ धोखा ही धोखा हो रहा है।

दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना की जरूरत नहीं:केजरीवाल

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार की आयुष्मान भारत योजना को बड़ा घोटाला बताते हुए देशभर में दिल्ली की बेहतरीन स्वास्थ्य मॉडल को लागू करने की सलाह दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह मेरा नहीं बल्कि कैग का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। इस योजना में इलाज के लिए मरीज़ को भर्ती होना जरूरी है, जबकि दिल्ली में भर्ती होने की कोई शर्त नहीं है, 5 रुपए की दवाई से लेकर 1 करोड़ तक का इलाज मुफ्त है। जब दिल्ली में दवाई, टेस्ट, इलाज सब फ्री है तो यहां आयुष्मान भारत योजना की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के हेल्थ मॉडल का अध्ययन कर इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना कहती है कि जब आप अस्पताल में भर्ती होंगे तब आपका 5 लाख तक का इलाज होगा, जबकि दिल्ली में हमारी योजना के तहत आपको सर्दी-जुकाम भी हो तो आप ओपीडी, आईपीडी में जाकर इजाल फ्री में करवा सकते हैं। आप भर्ती हो या न हो आपका सारा इलाज मुफ्त होता है। आपको पांच रुपए की क्रोसीन चाहिए या पचास लाख या एक करोड़ रुपए का इलाज कराना है। सब कुछ फ्री है। यहां कोई पांच लाख रुपए की लिमिट नहीं है। जब यहां दवाइंया, टेस्ट, ओपीडी, आईपीडी, रेग्यूलर चेकअप से लेकर सब कुछ फ्री है तो दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की योजना किसी व्यक्ति का 20 लाख रुपए का भी इलाज मुफ्त में होता है। हमारे मोहल्ला क्लीनिक में कोई जाता है तो उसका इलाज भी मुफ्त होता है। हम इसे कैसे बंद कर दें?

आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी के लिए हेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक ऐसा हेल्थ मॉडल पेश किया है, जिसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान को भी करनी पड़ी थी।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कैम बहुत ही विस्तृत स्कैम है। इसमें लगभग 26 हजार अस्पतालों का सूची में नाम लिखा गया है। जिसमें से करीब 7 हजार अस्पताल सिर्फ कागजों में हैं। 4 हजार अस्पताल ऐसे हैं, जिन्होंने आयुष्मान भारत स्कैम के तहत अब तक किसी को एडमिट ही नहीं किया है। जिन अस्पतालों ने आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों के लिए एडमिशन किए थे, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्योंकि मोदी सरकार उनका बकाया पैसा नहीं दे रही है।

प्रियंका कक्कड़ ने पेपर्स दिखाते हुए कहा कि हरियाणा की इंडियन मेडिकल असोसिएशन ने 29 फरवरी को केंद्र सरकार को लिखकर अवगत कराया था कि वो आयुष्मान भारत के तहत अब किसी और का एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि मोदी सरकार ने उनका बकाया पैसा नहीं दिया है। इंडियन मेडिकल असोसिएशन ने आखिरी लाइन में लिखा है कि सभी लंबित भुगतान चुकाएं जाएं वरना 26 मार्च 2024 से आयुष्मान कार्ड भी जारी नहीं किए जाएंगे। प्रियंका कक्कड़ ने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आज 50 फीसदी से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आते हैं। अगर आयुष्मान भारत इतनी बढ़िया स्कीम है तो वहां के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ रहा है? हालांकि, हम उन लोगों का स्वागत करते हैं।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हमारी सरकार अपने बजट का 16 फीसदी स्वास्थ्य को आवंटित करती है। वहीं, हेल्थ एलोकेशन नेशनल हेल्थ मिशन ने 2017 की पॉलिसी अपने पूरे बजट का 2.5 फीसदी आवंटित करती है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करेंगे। हम दिल्ली वालों के लिए हेल्थ केयर हमेशा मुफ्त रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसको और बेहतर किया जाए।